

चीन, रूस नॉर्थ कोरिया व ईरान, एस.सी.ओ. के नये "कोर ग्रुप" के रूप में उभरा

भारत, इस नई व्यवस्था का महत्वपूर्ण सदस्य तो है, पर "कोर ग्रुप" से अलग सा भी है

-अंजन राय-

अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-वाशिंगटन, 2 सितम्बर। शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) कभी ऐसा संगठन माना जाता था, जिसकी सालाना बैठक होती तो थी, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं होता था। तथापि, इस बार चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रही बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और यह एलान कर रही है कि एक नया वैश्विक ढांचा बन रहा है, और जो मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था, जो अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे में थी, अब पूरी तरह चीन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे साफ हो गया है कि चीन अब अमेरिका का असली मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है और यूरोप हाशिये पर चला गया है।

कोरियाई प्रजातंत्रों के प्रतिनिधि-वाशिंगटन, 2 सितम्बर। शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) कभी ऐसा संगठन माना जाता था, जिसकी सालाना बैठक होती तो थी, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं होता था। तथापि, इस बार चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रही बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और यह एलान कर रही है कि एक नया वैश्विक ढांचा बन रहा है, और जो मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था, जो अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे में थी, अब पूरी तरह चीन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे साफ हो गया है कि चीन अब अमेरिका का असली मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है और यूरोप हाशिये पर चला गया है।

- साहोदर व मैत्री के सार्वजनिक इजहार के बावजूद चीन व भारत के बीच कई भारी मतभेद भी हैं, जिनकी अनदेखी सदा के लिये नहीं की जा सकती।
- अतः अमेरिका व पश्चिमी देशों के समूह व चीन के नेतृत्व वाले एस.सी.ओ. संगठन के बीच भारत अकेला सा खड़ा है।
- कुछ ऐसी ही स्थिति रूस की है। जो, शीत युद्ध के जमाने के "सुपर पावर" के गरिमापूर्ण पद से अब केवल चीन की ओर देखने वाला राष्ट्र हो गया है। जो चीन की ओर, धन, हथियार व स्पेयर पार्ट्स के लिये देखता है। रूस, ईरान का भी आभारी है, क्योंकि ईरान द्वारा भेजे गए आधुनिक "ड्रोन्स" की उसे बहुत आवश्यकता है, यूक्रेन के "फायर पावर" का मुकाबला करने के लिये। नॉर्थ कोरिया भी "कोर ग्रुप" का महत्वपूर्ण सदस्य इसलिए है, क्योंकि, उसने रूस की तरफ से लड़ने के लिये कोरिया से अपने सैनिक भेजे हैं।
- एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि अमेरिका का प्रयास था, कि वह रूस को अलग-थलग कर देगा देशों की अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत से। पर, उल्टा हो गया। अमेरिका, अलग-थलग पड़ गया है, और यूरोप व पश्चिमी देशों के बाड़े में कैद हो गया है। तथा रूस, कमज़ोर ही सही "अन्य देशों" की मदद में आराम से बैठा है।

हो एक तरह से चीन के अधीनस्थ दिखाई दे रहे हैं। रूस अब चीन पर निर्भर रहने वाला देश बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति पतिन ने जो सपना देखा था, रूस को "शाही ताकत" को फिर से पाने और अमेरिका को टक्कर देने वाली

एकमात्र महाशक्ति बनने का, वह बिल्कुल उल्टा साबित हुआ है। अब रूस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से हमें हराने के लिए भाजपा की मदद की'

आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर खुला आरोप लगाया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली में भाजपा लम्बे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रतिद्वन्दी रही है। लेकिन आप ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले लगभग एक दशक से चुनावी रूप से हाशिये पर रही कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया। इस राजनीतिक टक्कर का जड़ दिल्ली नहीं, बल्कि पंजाब है, जो देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहाँ फिलहाल आप की सरकार है। आप ने कांग्रेस पर तीखा हमला दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के एक इंटरव्यू के बाद किया, जिसे आप के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साक्षा किया गया। वीडियो में यादव यह कहते हुए सुने गए कि पार्टी ने आप को हराने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा भाजपा को हुआ। यादव ने पार्टी

- उन्होंने कहा कांग्रेस ने आप को हराने के लिए आप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपने दिग्गज नेता खड़े किए जैसे केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित, मनीष सिंसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा गया।
- आप ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के इंटरव्यू के आधार पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।

की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, "अगर आप को हराना है, तो मनीष सिंसोदिया, और अरविंद केजरीवाल को हराना जरूरी है। इसमें हम कुछ हद तक सफल रहे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि अगर इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ तो क्या वह स्वीकार्य होगा तो यादव ने जवाब दिया, "सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यह बात खड्डो जी

और राहुल गांधी जी से हुई चर्चा में आई थी और हमने तय किया था कि हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।" इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रैस कॉन्फ्रेंस की ओर इसे एक "बड़ा रहस्योद्घाटन" बताया तथा उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आठ साल से भू-अभिलेख निरीक्षण पदोन्नति परीक्षा क्यों नहीं हुई?

जयपुर, 2 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आठ साल बाद भी पटवारी के पद से भू-अभिलेख निरीक्षण पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं

- हाईकोर्ट ने रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार को 8 सितंबर को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये।

होने पर रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने 8 सितंबर तक को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बोर्ड ने साल 2017 के आदेश और 7 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी होने पर भी विभागीय पदोन्नति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित क्यों नहीं कराई। जस्टिस महेन्द्र गौयल ने यह आदेश विवेक शर्मा की याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2017 को सतीश सिंह बनाम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारी के बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ'

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 11 सितंबर को याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने का दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किया जाए। ऐसा

- हाईकोर्ट ने कहा 11 सितंबर तक भुगतान करें या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों।

नहीं करने पर अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत ने को बताया कि अदालती आदेश की पालना में वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1997 से सेवा में नियमितकरण का लाभ दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चन्द्रबाबू नायडू के राजनीतिक जीवन के तीस साल पूरे होने पर जश्न का माहौल क्यों नहीं है एन.डी.ए. में?

भाजपा चौकड़ी है, क्योंकि एक तरफ तो बिहार चुनाव का "टैशन" है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मौके पर दरारें उभर रही हैं, एन.डी.ए. में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसा राजनीतिक मुकाम जिसने नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। जहां टीडीपी इस अवसर पर जश्न मना रही है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में इसे राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में, जब मोदी सरकार आंतरिक असहमति और बाहरी चुनौतियों से जूझ रही है।

टीडीपी के जश्न की राजनीतिक टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि केन्द्र सरकार जहां एक ओर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कठिन चुनौती का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर, उपराष्ट्रपति चुनाव भी अप्रत्याशित रूप से पेचीदा हो गया है। ऐसे माहौल में, नायडू की आक्रामक राजनीतिक मुद्रा ने उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि वर्तमान उथल-पुथल की जड़ 130वां संविधान संशोधन

- नायडू के करीबी सलाहकार सरकार द्वारा संसद में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त सांसदों, मंत्रियों की सदस्यता खत्म करने के संबंध में पेश विधेयक को भी संशय कि दृष्टि से देख रहे हैं, और प्रचारित कर रहे हैं की इस विधेयक को लाने का मुख्य ध्येय, चन्द्रबाबू नायडू के पर कतरना है।

- सांसदों में इस विधेयक को लेकर फैली बेचैनी के दौरान नायडू की भूमिका काफी "निर्णायक" हो जाती है और नायडू की, राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उच्चतम पद की आशाएं जगाना कोई, असंभव बात नहीं है। अगर इस गफलत में नये राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो चन्द्रबाबू नये "कॉम्प्रोमाइज़" उम्मीदवार बन सकते हैं, उच्चतम पद के लिये।

विधेयक है, जिसे लोकप्रिय रूप से "क्रैडिलिटी बिल" बताया जा रहा है। टीडीपी सूत्रों के अनुसार, नायडू इस विधेयक से खुश नहीं हैं, और यह असंतोष पार्टी के सांसदों तक भी पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के बहुत से लोग इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नायडू पर दबाव बनाने का साधन मान रहे हैं, ताकि उनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच को नियंत्रित किया जा सके।

नायडू के करीबी रणनीतिकारों ने संकेत दिए हैं कि टीडीपी प्रमुख वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देख रहे हैं। भाजपा के भीतर असंतोष और एनडीए में उभरी दरारें उभरने के बीच, गठबंधन समीकरणों में फेरबदल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। टीडीपी के एक नजदीकी सूत्र ने नायडू की लम्बे समय से पोषित राष्ट्रीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील की जमानत याचिका खारिज की

ये दोनों 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मुख्य आरोपी हैं

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं एक बार फिर खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिन्द्र कौर को पीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी अपीलों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के लिए यह छठी बार था जब उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। इससे पहले वे तीन बार सत्र न्यायालय, दो बार दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें याचिका वापस लेनी पड़ी थी।

- दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कहा कि उन्होंने साजिश रचकर दंगा भड़काया था, देश की छवि खराब करने के लिए। बेहतर होगा कि बरी होने तक वे जेल में ही रहें।

- जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद का जमानत पाने का यह छठा असफल प्रयास था।

इस मामले में अन्य आरोपियों में अथर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। उमर खालिद ने गत माह अपना 38वां जन्मदिन पिछले महीने तिहाड़ जेल में मनाया, जहां वे पिछले पांच वर्षों से बंद हैं। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट ने उमर और अन्य आरोपियों की वर्ष 2022, 2023 और 2024 में दायर

जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब खारिज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था, अगर आप देश के खिलाफ कुचक्र कर रहे हैं, तो जब तक आप बरी नहीं होते या दोषी नहीं ठहराए जाते, तब तक आपको जेल में रहना चाहिए। राजधानी में दंगे हुए, जिनमें 100 पुलिसकर्मी और 41 अन्य घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की जान गई।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थे, जिनका उद्देश्य समाज में विघटन और अराजकता फैलाना था।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर पैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

अफगानिस्तान में 24 घंटे में ही दूसरा भूकंप

काबुल, 02 सितंबर। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से मरने वालों की संख्या

- भूकंप से अब तक 1411 की मौत हो गई हैं और 3250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.5 थी।

अब तक 1411 हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 3250 से ज्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनियाभर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही, 15 टन खाने का सामान, काबुल से कुनार भेजा। भारत की ओर से अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए भेजी गयी सहायता सामग्री मंगलवार को काबुल पहुंच गयी। हाई मार्ग से भेजी गयी सहायता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. दीपक मित्तल यूई में भारत के राजदूत नियुक्त

नयी दिल्ली, 02 सितम्बर। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉ. दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह बताया कि डा.मित्तल विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं और उनके शीघ्र ही

- 1998 बैच के अफसर डॉ. मित्तल इससे पहले कतर में भारत के राजदूत थे।

कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। वह कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। डॉ. मित्तल संजय सुधीर की जगह लेंगे जो अब तक संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत थे। वर्ष 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उन्होंने भारत और तालिबान शासन के बीच औपचारिक संपर्क शुरू कराने में अहम भूमिका निभायी थी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मेरे पास तमिनलाडु व केरल का "चार्ट" है, जब राज्यपाल ने कब-कब कितना विलम्ब किया, विधेयक को स्वीकार करने में'

अभिषेख मनु सिंघवी, के इन दावों के प्रत्युत्तर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मेरे पास भी अन्य राज्यों का चार्ट है, जहां कब-कब राज्यपाल ने कितनी देरी लगाई अपने सहमति देने में

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल की शक्तियों के मामले में उसका निर्णय इस पर निर्भर नहीं करेगा कि केंद्र या राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है। अदालत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए उस संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाया गया है। इस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा तय की गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंद्रकर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह

- मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा, सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मंच न बनाये, अपने राजनीतिक सोच को प्रकट करने के लिये।
- सुप्रीम कोर्ट में, राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक के बारे में अपना निर्णय देने के लिये समय निर्धारण का मामला था।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, किस राज्यपाल ने कितना विलम्ब किया, अपना निर्णय देने में, ऐसे चार्ट प्रस्तुत करना कोई सम्मानजनक बात नहीं है, यह मामला आखिरकार, राष्ट्रपति मुर्मू ने कानूनी स्थिति की व्याख्या करने के लिये सुप्रीम के सम्मुख भेजा है। पर अगर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो भी तैयार हूँ।
- सिंघवी ने प्रत्युत्तर में कहा, "मिस्टर मेहता धमकी नहीं चलेगी।"

संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, हम इस मुद्दे पर निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों या सत्ता में कौन है, या कौन था इस आधार पर

नहीं करेंगे। यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेख मनु सिंघवी (तमिलनाडु राज्य की ओर से) और सॉलिसिटर जनरल तुषार

मेहता (केंद्र सरकार की ओर से) राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के मामलों पर आंकड़ों को लेकर बहस कर रहे थे। सिंघवी ने कहा, मेरे पास

तमिलनाडु और केरल के आंकड़े हैं, इस पर मेहता ने विरोध किया और कहा कि उनके पास अन्य राज्यों के आंकड़े भी हैं। उन्होंने कहा, अगर वह गंदे रास्ते पर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह एक राष्ट्रपतीय संदर्भ है। जवाब में सिंघवी ने कहा, धर्मकार्यों से कुछ नहीं होगा। सिंघवी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेहता सर्वैधानिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 200 किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।

अस्तित्व में आने के समय से था। गवई ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि यह मंच राजनीतिक बहस का अड्डा बनो। यह राष्ट्रपतीय संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल के फैसले के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को विधेयकों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा और सर्वैधानिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 200 किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।

विचार बिन्दु

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शक्ति का आश्रय लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भौतिक शरीर इस आत्मा को धारण करने के लिए विवश होता है। -गेटे

धर्मांतरण का आपराधिक कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को 3 फरवरी, 2025 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था। अब घोषणा की गई है कि उसे पारित करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने उसे और अधिक कठोर बनाया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबर्न धर्म परिवर्तन को रोकना बताया गया है। विधेयक में अवैध धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर-जमानतो अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपराधियों को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का परिचय जबर्न धर्मांतरण के उन्नाहते मामलों को रोकने की व्यवस्था के रूप में दिया गया है, जिसे इन दिनों 'लव जिहाद' कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल भाजपा और उसके सहयोगी उन मामलों का वर्णन करने के लिए करते हैं जहां मुस्लिम पुरुष कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से विवाह उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए करते हैं। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक कमजोर व्यक्तियों को धर्मांतरण से बचाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नये कठोर विधेयक को मंजूरी देना शासनरुद्ध दल के अति उत्साह को दर्शाता है। हालांकि, ऐसे विधेयक का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक विभाजन पैदा करने के ब्यापक एजेंडे का हिस्सा है किन्तु सरकार का तर्क है कि यह कानून राज्य में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य धर्मांतरण से जुड़ी जटिलताओं से निबटना है।

राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का पहला प्रयास 2006 में किया था, जब भाजपा नेता वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सत्ता में आई थीं। राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2006 का उद्देश्य बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना था। कांग्रेस, मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों ने यह कह कर उसका विरोध किया था कि यह कानून हिंदू समूहों को खुश करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने वह विधेयक वापस कर दिया था। फिर 2008 में, संबंद्धित जिला कलेक्टर को पूरा स्वीकृति अनिवार्य करने सहित नए प्रावधानों के साथ विधेयक का संशोधित संस्करण भी केंद्र के पास अटका रहा। राजे ने मुख्य मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल (2013-2018) में 2008 के विधेयक को लागू करवाने की कोशिश की और उसे केंद्र के सामने रखा, जिसने नवंबर 2017 में यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह राष्ट्रीय नीति से भटक गया है। कानून के अभाव में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 में जबर्न धर्मांतरण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। वैसे धर्मांतरण विरोधी कानून, जिन्हें अक्सर "धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है, का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में पहली बार 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हिंदू रियासतों द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों के सामने हिंदू धार्मिक पहचान को बचाने के प्रयास के रूप में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किये गये थे। स्वतंत्रता के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए कई प्रयास होते रहे हैं। पहला प्रयास 1954 में किया गया जब भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के लाइसेंस और धर्मांतरण के पंजीकरण को लागू करना था। इसके बाद, संसद में कुछ और निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हो सका क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका। वर्ष 2015 में, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कानून बनाने के खिलाफ सलाह दी। उसका कहना था कि केंद्र द्वारा कानून बनाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत धर्म पूरी तरह से राज्य का विषय है। बाद में इसलिए, कई राज्य सरकारों ने बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से किए गए धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए "धर्म की स्वतंत्रता" अधिनियम बनाए हैं। वर्तमान में 12 राज्यों में ऐसे अधिनियम लागू हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ कुछ प्रदेश हैं। इन राज्य-स्तरीय कानूनों के सामान्य प्रावधानों में धर्मांतरण की अनिवार्य रूप से पूर्व सूचनादेना, 'प्रलोभन' के लिए दंड और आरोपी पर सबूत का भार स्थानांतरित करना शामिल है। इन कानूनों का घोषित उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और कमजोर आबादी की रक्षा करना है, लेकिन इनकी अस्पष्ट परिभाषाओं, दुरुपयोग और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए आलोचना होती रही है।

अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, तब भी जब अंतरधार्मिक विवाह संबंधों के खिलाफ सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियां उठती हों। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी उन प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो अंतरधार्मिक संबंधों की अनुचित जांच करते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे धर्मांतरण की पूर्व सूचना की आवश्यकता, जबर्दस्ती और प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण भय और दमन का माहौल बन रहा है, जिससे व्यक्ति अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

संदर्भित करता है। अदालत निर्णय ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से भी जोड़ा, और कहा कि जबर्न धर्मांतरण से अशांति हो सकती है, जो संविधान की सत्तवी अनुसूची (प्रविष्टि II, सूची II) के अनुसार राज्यों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं के साथ संतुलित करते हुए संवैधानिक पाया। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता की आधुनिक व्याख्याओं से पहले का है, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में व्यक्त किया गया है। ऐसे कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का भी प्रतिकार करते हैं और इसलिए इन्हें अनुचित और असंवैधानिक कहा जाता है।

अब नई परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों के हालिया निर्णयों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक जोड़ों से जुड़े मामलों में। इन न्यायालयों ने पाया है कि ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन से कई बार उन व्यक्तियों को परेशान किया गया है और निशाना बनाया गया है जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया या अन्य व्यक्तिगत कारणों से धर्मांतरण करना चुना है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है जहां अंतरधार्मिक विवाहों को रद्द करने या सहमति देने वाले व्यक्तियों को अपराधी बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, तब भी जब अंतरधार्मिक विवाह संबंधों के खिलाफ सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियां उठती हों। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी उन प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो अंतरधार्मिक संबंधों की अनुचित जांच करते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे धर्मांतरण की पूर्व सूचना की आवश्यकता, जबर्दस्ती और प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण भय और दमन का माहौल बन रहा है, जिससे व्यक्ति अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

अनुभव बताता है कि जबर्न या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के वास्तविक मामलों को संबोधित करने का जब राज्य प्रयास करता है तब अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण होता है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक विवाहों के संदर्भ में। पहले ऐसे कानून के निशाने पर ईसाई होते थे अब मुसलमान हैं। भारतीय समाज को सामूहिक धर्म परिवर्तन की समस्या ईसाई मिशनरियों से रही। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की समस्या सामूहिक धर्म परिवर्तन की न होकर अंतरधार्मिक विवाहों के लिए लव जिहाद का नाम देकर ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि यह सामूहिक धर्म परिवर्तन का छद्म रूप है। हमारे यहां तो अपनी जाति से बाहर भी विवाह की इजाजत परंपरागत समाजों में नहीं है। ऐसे विवाहों पर जातियों की खापों के फैसले दिल दहला देने की हद वाले होते भी सबने देखे हैं। इसीलिए यह चिंता व्यक्त की जाती है कि इस प्रकार के कानून धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। असल बात यह है कि हम कैसे समाज बनाया चाहते हैं? हमारे संविधान की उद्घोषणा है, हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंचनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के वास्ते विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; हंसित्य और अवसर की समानता, और उन सभी के बीच बढावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। ऐसा संविधान सम्मत समाज बनाने की ही आज सबसे अधिक जरूरत है।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



अशोक कुमार

शिक्षा की अवधारणा केवल तथ्यों और आँकड़ों के संचय तक सीमित नहीं है; यह एक उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के लक्ष्यों को आकार देती है और उसे आगे बढ़ाती है। इसका वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना और उसके जीवन को प्रगतिशील, सांस्कृतिक और सभ्य बनाना है। यह व्यक्ति और समाज, दोनों के आंतरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली त्रि-ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक, छात्र और सामाजिक वातावरण (पाठ्यक्रम सहित) तीन मुख्य स्तंभ हैं। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की मात्रा बढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को एक स्वस्थ और समृद्ध संसार के लिए तैयार करना, उनकी सोच को विकसित करना और दूसरों को बातों को गहराई से समझने में सक्षम बनाना है।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शिक्षा का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के सर्वांगीण लक्ष्यों को प्राप्त करना रहा है। आधुनिक समय में भी, कोटारी आयोग जैसे विभिन्न आयोगों ने राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने और नैतिक मूल्यों के विकास जैसे व्यापक लक्ष्यों को

निर्धारित किया है। हालाँकि, एक गहरा विरोधाभास यह है कि जहाँ हम सैद्धांतिक रूप से सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वहीं व्यवहार में हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य ध्यान केवल रोजगार-केंद्रित हो गया है। यह असंतुलन लक्ष्य-विहीन शिक्षा को जन्म देता है, जो अंततः शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और गहरा करता है। वर्तमान संरचना और नीतिगत ढाँचा स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 के पारंपरिक पैटर्न पर संरचित रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 5+3+3+4 की नई पाठ्यचर्या प्रणाली अपनाकर इस ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन पर विशेष जोर देना है। यह एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के आँकड़े लगातार छात्रों में बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कौशल की कमी को दर्शाते हैं, जो नीतियों और उनके जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करता है।

सार्वजनिक शिक्षा: वित्तपोषण और संस्थान बाधाएँ

यह एक आम धारणा है कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करती है, और आँकड़े इस धारणा को बल देते हैं। यद्यपि शिक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है (2025-26 के लिए अनुमानित 1,28,650 करोड़), लेकिन यह वृद्धि ग्रामिक हो सकती है। पिछले चार वर्षों से, शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय (केंद्र + राज्य) समस्त घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2.9% पर स्थिर बना हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित 6% के लक्ष्य से बहुत कम है। यह दर्शाता है कि शिक्षा पर खर्च

केवल समग्र आर्थिक विस्तार के साथ तालमेल बिटा रहा है, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कोई विशेष बढ़ावा नहीं मिला है।

इस समस्या को राज्यों का खराब राजकोषीय स्वास्थ्य और गहरा करता है, क्योंकि शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग 76% राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। अपर्याप्त वित्तपोषण का सीधा प्रभाव संस्थागत गुणवत्ता पर पड़ता है:-

शिक्षकों की कमी: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 35%, एसोसिएट प्रोफेसरों के 46% और सहायक प्रोफेसरों के 26% पद रिक्त हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: UDISE (2019-20) के आँकड़ों के अनुसार, केवल 12% स्कूलों में इंटरनेट और 30% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। 23% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। गुणवत्ता में गिरावट: अपर्याप्त संसाधन, शिक्षकों की कमी और पुरानी शिक्षण विधियों के कारण सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे वे निजी संस्थानों के सामने अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं।

निजी क्षेत्र का उदय और संबंधित चिंताएँ

सार्वजनिक शिक्षा की इन्हीं कमियों के कारण पिछले दो दशकों में निजी शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। 2021-22 में, कुल स्कूलों में से 32% से अधिक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल थे। सरकार ने भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं, जिसकी पूर्ति सरकार करती है। हालाँकि निजीकरण ने विकल्प प्रदान किए हैं, लेकिन इसने गंभीर

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी जन्म दिया है। निजी स्कूलों की भारी फीस उन्हें अधिकांश आबादी की पहुँच से बाहर कर देती है, जिससे एक समानांतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण होता है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल उन्हीं को मिलती है जो इसका खर्च उठा सकते हैं।

गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीतिक रोडमैप

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक शक्तिशाली सबक प्रदान करती है। वहाँ की सफलता का आधार निजीकरण नहीं, बल्कि एक मजबूत, समान और पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित प्रणाली है। फिनलैंड की सफलता के स्तंभ हैं: शिक्षक बनाम एक अत्यंत प्रतिष्ठित पेशा है और शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। समग्र मूल्यांकन: ग्रेडिंग और उच्च-दर-दर-दर परीक्षाओं के बजाय सीखने की प्रक्रिया और मौखिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। समान अवसर: सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को परवाह किए बिना, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है।

इसके विपरीत, भारत में यह धारणा है कि केवल निजीकरण ही गुणवत्ता ला सकता है। हालाँकि, राजस्थान की आदर्श योजना इस धारणा को चुनौती देती है। इस सरकारी पहल के माध्यम से, प्रणालीगत सुधारों, बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और शिक्षक रिक्रियों को धरकर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में इतना सुधार किया गया कि नार्मानकन में लगभग 700,000 छात्रों की वृद्धि हुई, जिनमें से कई छात्र निजी स्कूलों से वापस आए। यह साबित करता है कि रणनीतिक निवेश और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा

सकता है।

नीतिगत और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है: वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाना: सरकार को शिक्षा पर अपना बजटीय व्यय GDP के अनुशंसित 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह केवल आवंटन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में भी है। शिक्षक सशक्तिकरण: शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरना, उन्हें नियमित और आकर्षक वेतन देना, और उन्हें विश्व स्तरीय सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षकों को फिनलैंड की तरह अधिक स्वायत्तता और सम्मान देना होगा। NEP 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन: रटने की संस्कृति को समाप्त करने और महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समरथा-समाधान जैसे 21 वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मूल्यांकन को सुधार: पारंपरिक परीक्षाओं से हटकर, मूल्यांकन को PARAKH (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन का आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से नियमित, रचनात्मक और दक्षता-आधारित बनाया जाना चाहिए। निजी शिक्षा का सख्त विनियमन: निजी स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है ताकि वे शिक्षा के मिशन से विचलित न हों।

-अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं
गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व
विभागाध्यक्ष, राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर

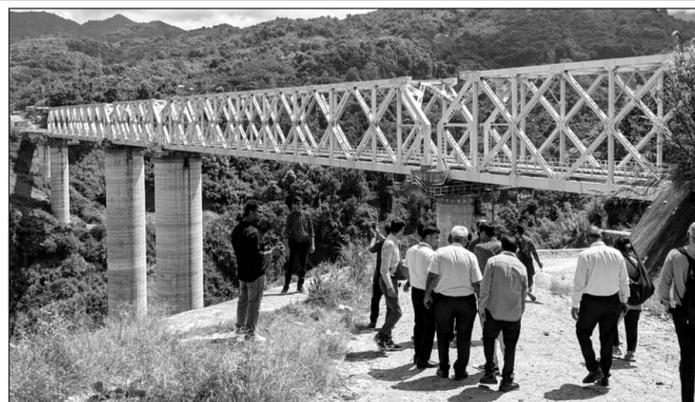
आजादी के बाद पहली बार रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है "आइजोल"

राजस्थान के पत्रकारों के दल को आइजोल में इस रेल से यात्रा कराई

आजादी के इतने वर्षों बाद मिजोरम के लोगों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने जा रहा है। आइजोल पहली रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कर्पिजल किशोर शर्मा ने बताया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगत देने वाले हैं। इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजस्थान के पत्रकारों के दल को इस रेल से यात्रा कराई गई।

ये रेल लाइन आइजोल को पूरे देश से जोड़ेगी। पहले ये आइजोल को असम के सिलचर से जोड़ेगी। फिर वहाँ से पूरे देश के साथ कनेक्ट होगी। इस रेलवे रुट में 48 सुरंगें, जिनकी लंबाई 12.8 किमी और 55 बड़े पुल शामिल हैं। इसके साथ ही 87 छोटे पुल भी बने हैं। यह पुल एक पिल्लर पर पर भारत का सर्वोच्च पल्लो पुल है। इसमें पुल की ऊंचाई 114 मीटर है। यह प्रोजेक्ट मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ेगी और पूर्वी क्षेत्र में व्यापार के साथ पर्यटन को एक नई दिशा देगा।

गौरलब है कि सैरंग रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास पैसिलिटि सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है।



इसके बाद इस रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सेवा भी शुरू की जाएगी। ये रेल प्रोजेक्ट केंद्र की एक ईस्ट पाँसिरी का पथ है, जो करीब 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। इसका मकसद उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अपनी ऊँची एवं हरी-भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर को अपने आंचल में समेटे पहाड़ों की नगरी आइजोल भारत के अग्रणी पर्यटन स्थलों में से एक है।

अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा होने से विश्व पर्यटन क्षेत्र में आइजोल अपनी खूबसूरती का लाभ नहीं मिल पाया है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर मिजोरम के उत्तरी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से 1132 मीटर (3715 फीट) ऊँची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके पश्चिम में त्लावंग नदी घाटी और पूर्व में तुइरियल नदी घाटी बहती है। अब आइजोल रेलमार्ग से जुड़ने जा रहा है। स्थानीय निवासियों में रेलमार्ग से जुड़ने की खुशी छाई हुई है। इनका उत्साह देखते बनता है। स्थानीय एक व्यक्ति ने

कहा कि हम रेल से जुड़ने जा रहे हैं। इसकी खुशी किसी पर्व से कम नहीं है। पर्यटन में हम आसमान छूने वाले हैं। गौरलब है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित मिजोरम एक दर्शनिय और सांस्कृतिक रूप से जीवंत राज्य है। इसकी सीमायें म्यांमार, बांग्लादेश और भारतीय राज्यों त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती हैं। "पहाड़ी लोगों की भूमि" के रूप में प्रसिद्ध मिजोरम की विशेषता इसके घुमावदार पहाड़ियाँ, घने जंगल और उल्लेखनीय जैव विविधता है। मिजोरम कई जातीय समूहों को वास्तव्यभाव से अपने में समेटे हुए है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता,

इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे

सांस्कृतिक समृद्धि और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ, मिजोरम एक स्थायी और शांत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अपार संभावनाएँ हैं। अपने मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के कारण मिजोरम के आने वाले समय में भारत का सिरमौर पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। मिजोरम बाँस और बेंत की कारीगरी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। हस्तशिल्प के लिए भी यहाँ का अलग ही रुतबा है। वस्त्र, बाँस, बेंत की कारीगरी और टोकरा बनाया शिल्पकला यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है। कई महिलाएँ बुनाई और टोकरा बनाने का काम करती हैं, जबकि बाँस और बेंत का उद्योग फल-फूल रहा है। रेल मार्ग से जुड़ जाने के बाद यहाँ के अन्य उद्योगों को भी फलने फूलने का अवसर मिल जाएगा। आइजोल के मुख्य पर्यटन स्थलों में आइजोल पीक, डर्टलैंग हिल्स, चनमारी, टामदिल, और हमुईयांग शामिल हैं। प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम पर्यटकों को आनन्द प्रदान करता है।

-मिश्रीलाल पंवार।

राशिफल बुधवार 3 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वाषाढा नक्षत्र रात्रि 11:44 तक, आयुष्मान योग सायं 4:17 तक, वणिज करण सायं 4:07 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरु-मिथुन, शुक-कर्क, शनि-मीन, राहु-सिंह, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:08 तक है। भद्रा सायं 4:07 से रात्रि 4:22 तक है। आज पदमा एकादशी व्रत, जल झूलनी और पतिवर्तनी एकादशी, डोल यारस पर्व है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 10:52 से 12:26 तक, चर्य:3:34 से 5:08 तक, लाभ 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:42

मेघ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विचम्ब हो सकता है। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियाँ हूँ दूर लगेगी। मन का भय समाप्त होगा। विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य स्थिर हो सकते हैं।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगी।

धनु
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोते से धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक

बजट घोषणाओं के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

■ प्रदेश में 18 सितम्बर से शुरू होगा "गांव चलो" अभियान

जाए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन, डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर विकास कार्यों का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नंस के मानकों पर खरा उतरते हुए जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग तकनीक और नवाचार के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है। किसानों को स्वयं फसल गिरावरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि

अधिक से अधिक किसानों को इस एप से जोड़ा जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन "गांव चलो" अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित लंबित राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अभियान के लाभ

से वंचित न रहे। बैठक में भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के बजट में घोषित भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

उन्होंने पुराने भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। जैसलमेर जिले में सामान्य आवंटन से जुड़े लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण की बात भी कही गई।

अधिकारियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक 87 प्रतिशत किसानों को फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ने का कार्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। भू-नक्शा पोर्टल पर अब तक राज्य के 48,463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल अपलोड कर

4.49 करोड़ यूनिट लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं।

बैठक में रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, सरकारी अधिवक्ताओं को रिटर्न शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में संशोधन, ग्राम दान और भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विधियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

माँ के अपमान पर जयपुर भाजपा ने हुंकार भरी

छोटी चौपड़ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया



भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर धरना देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर विशाल धरना तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूज्य माता के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के खिलाफ 3 घंटे चले इस धरने में भाजपा के सभी कार्यकर्ता विधायक व अन्य नेताओं ने अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को तीखी आलोचना की। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने भारत माँ के जयकारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की।

जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कहे गए अपशब्द केवल एक माता का नहीं, बल्कि समस्त मातृ शक्ति एवं भारतीय संस्कारों और संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान है।

माँ के अपमान पर जयपुर की नारी चुप नहीं रहेगी। माँ सीता का अपमान होने पर सोने की लंका जला दी गई थी। माँ को भरी सभा में घसीटा गया, तो महाभारत हुई। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को माँ का अपमान हुआ है

■ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय माँ के खिलाफ इन दोनों नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की

■ "माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान" तथा "माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई मातृशक्ति

और सभी को भारत माता के नारे लगवाए। धरने में जयपुर के विभिन्न कोनों से आई सैकड़ों की संख्या में नारी शक्ति भी उपस्थित रही।

वे "माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान, "माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई। इस अवसर पर अनेक विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को घोर निंदा की।

इस अवसर पर सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल से विधायक बालमुकुंदचार्व, किशनगोल प्रत्याशी चंद्रमोहन बेंदवाडा, महापौर कुसुम यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बाड़ी, प्रदेश मंत्री अजीत माण्डन, प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक, पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, अपूर्वा सिंह, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, सहित अनेक पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष, सही समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

अतिवृष्टि, फसल खराबे और लाॅ एण्ड ऑर्डर पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक

जयपुर। राजधानी जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोक से विधायक सचिन पायलट भी शरीक हुए।

बैठक में रणनीति बनाई गई कि, राजस्थान में अतिवृष्टि से बिगड़े हालातों, फसल खराबे और प्रदेश में लाॅ एण्ड ऑर्डर को लेकर सदन में भाजपा सरकार को घेरा जाए। बैठक में करीब-करीब सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने के निर्देश दिये।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि पूरा विपक्ष जनसमस्याओं

को विधानसभा में उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने बैठक में बताया है कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गरीबों के कच्चे मकान ढह रहे हैं, खेतों में पानी भरने से किसान बर्बाद हो गये हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों को हालत बदतर है। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई राहत पहुंचाने का कार्य नहीं किया है।

शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़, अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने तथा झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है। सरकार पंचायतीराज और निकाय चुनाव करवाने से बच रही है। परिसीमन के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिला व बालिका अत्याचार के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई

है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस, सदन में राज्य सरकार को घेरेगी।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राजस्थान की भजनलाल सरकार, इनका रवैया यही रहा है कि ये लोग मुझे पर बात ही नहीं करना चाहते। प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सदन में सार्थक चर्चा चाहती है।

उन्होंने कहा कि हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि हम उनकी समस्याओं पर सदन में चर्चा करें। भजनलाल सरकार ने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे।

याचिका खारिज

जयपुर। हाईकोर्ट ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और निर्यंत्रक पद पर डॉ. दीपक माहेश्वरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपिठ ने यह आदेश डॉ. अवतार सिंह दुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दीपक माहेश्वरी की ओर से साल 2016 में दिए त्यागपत्र और उसे वापस लेने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को जानकारी होने के भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर सात साल पहले दिए इस्तीफे और उसे वापस लेने की अनुमति देने पर आपत्ति उठा रहा है।

विदेशी पर्यटकों के लिए जी.एस.टी. हटाने की मांग

जयपुर (कासं)। इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपकर विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है। इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे को भरपाई में भी मदद मिलेगी। यह बात आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल, कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने मंगलवार को अलसीसर हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।



अलीसार ने बताया कि पिछले वर्ष हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए की गई आईएचएचए की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अपने बजट में घोषित भी कर दिया गया है। साथ ही, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

आईएचएचए कमेटी सदस्य, शंजुन सिंह ने कहा कि इस वर्ष के आईएचएचए कन्वेंशन की थीम रोमांटिक हैरिटेज है। हैरिटेज प्रॉपर्टीज में स्वाभाविक रूप से रोमांस की भावना समाहित होती है, जो उनकी कलिनरी परम्पराओं, म्यूजिक,

■ इंडियन हैरिटेज होटल्स एसो. का 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग 6-7 सितंबर को होगी

भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान संजीव विद्याधी द्वारा रिवाइवल ऑफ हैरिटेज आर्किटेक्चर विषय पर चर्चा आयोजित होगी। इसके पश्चात, अर्पिमय्यु सिंह अलसीसर द्वारा राजस्थान के आलोक संगीत पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वीर विजय सिंह डुंडलोद द्वारा होटल ऑपरेशंस पर एक संवाद और सोलर एज टेक्नोलॉजीज द्वारा एक प्रजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। दिन के दौरान एजीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे और सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस बैठक में केवल एजीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हिस्सा लेंगे।

एलआईसी की बीमा बाजार में 65.83 प्रतिशत हिस्सेदारी

जयपुर। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) अपनी 69वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। एलआईसी ने 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय ब्रांड के रूप में भी उभरी है। गत 1 सितंबर 2025 को अपनी 69वीं वर्षगांठ का गौरवशाली क्षण मना रही एल.आई.सी. ने अपनी उपलब्धि का

श्रेय टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत तथा ग्राहकों के विश्वास को दिया है। एल.आई.सी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पॉलिसियों में 65.83 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 57.05 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। कुल एयूएम 6.45 प्रतिशत बढ़कर 54.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

बीमा निगम 35 व्यक्तिगत उत्पादों, 12 समूह उत्पादों, 7 व्यक्तिगत राइडर्स और 1 समूह राइडर का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो समाज के हर वर्ग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस, एयुटी प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ और यूनिट लिंक्ड उत्पाद। ये योजनाएं ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।

सचिन पायलट ने जैसलमेर पहुंचकर कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि दी

ए.आई.सी.सी. महासचिव पायलट ने, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के विवाद को लेकर राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा

जयपुर/जैसलमेर (कासं)। ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचकर पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतुष्ट परिजनों को ढांडस बंधाया। पायलट के साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। जब पायलट विशेष विमान से जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमदे सिंह तंवर, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अदुल्ला फकीर व अंजना मेघवाल और सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिन पायलट पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के जैसलमेर आवास पर पहुंचे। जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले पर राज्य सरकार पर चुबानी हमला बोला। पायलट ने कहा कि, प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है।



ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचकर पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतुष्ट परिजनों को ढांडस बंधाया।

■ पायलट ने कहा कि "एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था, परंतु राजस्थान सरकार कभी कहती रही कि है कमेटी बना दी... समिति बना दी। लेकिन हकीकत में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।"

राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इस पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी बार-बार कहा है, आज भी दोहरा रहा हूँ कि यह समस्या मात्र एक परीक्षा की नहीं है, अपितु इस पूरे सिस्टम की है। आर.पी.एस.सी. को गंगाजी है, जहां से परीक्षाएं व इंटरव्यूज होते हैं और नौकरि लगती है। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि आर.पी.एस.सी. में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में उन सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर भी संदेह होता है।

आपके घर हूपर नहीं आ रहा तो क्यूआर कोड स्कैन करे



जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में "वॉयसेज ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी" अभियान के तीसरे न्यूजलेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया। इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2025 को की थी। "वॉयसेज ऑफ

ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद भी वकील को क्यों दिखाया असफल?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद वकालत कर रहे वकील को अब इस परीक्षा को पास नहीं करने वालों की सूची में शामिल करने पर बार कौंसिल ने कहा है कि सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होकर प्रकरण से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश भागीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने अदालत को बताया कि बीसीआर ने साल 2012 में याचिकाकर्ता का नामांकन पर स्थाई वकालत के लिए उसे प्रमाण पत्र जारी किया गया। वहीं बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 के नियमों को लागू करते हुए साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम आयोजित किया। जिसमें याचिकाकर्ता शामिल होकर परीक्षा में पास हुआ। इस पर याचिकाकर्ता ने बीसीआई से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र मांगा। जिस पर कौंसिल ने उससे ढाई हजार रुपए का शुल्क जमा करवाया। याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने एक सूची जारी कर ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करने वाले वकीलों को प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल किया गया, जबकि वह पूर्व में ही यह परीक्षा पास कर चुका है। याचिका में कहा गया कि इसकी शिकायत बार कौंसिल ऑफ इंडिया में करने पर उसे सूचित किया गया कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हुआ था। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसे पहले पास बताया गया और प्रमाण पत्र जारी करने के बदले फीस भी ली गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीआर के सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।

स्वच्छता अभियान को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : के.के. गुप्ता

न्याय मित्र के.के. गुप्ता मंडावा दौरे पर रहे, सीवरेज कंपनी व पालिका कर्मचारियों के साथ बैठक ली

मंडावा, (निर्स)। जिला लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के के गुप्ता मंगलवार को मंडावा दौरे पर रहे। नगर पालिका में गुप्ता ने सीवरेज कंपनी व नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बैठक कर जन समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुप्ता ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर यहां की जनता और सैलानियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसको लेकर सीवरेज का काम करवाया, लेकिन जनता त्रस्त अधिकारी मस्त यह कहावत यहां पर सटीक बैठ रही है। इस समय सीवरेज कार्यों में लापरवाही सामने आ रही है। जो गंधीर मुद्दा है जगह-जगह सीवरेज चैंबर ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन कोई स्थाई समाधान नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण आम जनता परेशानी झेल रही है। इसके लिए नगर पालिका व संबंधित कंपनी जिम्मेदार है। गुप्ता ने कहा कि सीवरेज कार्यों की जांच को लेकर सरकार व न्यायालय को अवगत करवाया जाएगा तथा अब तक हुए कार्यों की जांच करवाई जाएगी तथा



न्याय मित्र के. के. गुप्ता ने मंडावा में सीवरेज कंपनी व पालिका कर्मचारियों के साथ बैठक ली।

मेंटेनेंस धुगतान रोकने को लेकर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी तैयार रहें। सात दिन में समाधान नहीं करने पर सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी ब्लैक लिस्ट जैसी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर न्याय मित्र ने जहां पर सीवरेज का कार्य पूर्ण हो गया है, वहां पर नालियों को बंद करने के निर्देश नगर पालिका को दिए तथा नगर पालिका से सर्वे रजिस्टर गायब मामले

को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए। गुप्ता ने कहा कि सर्वे रजिस्टर गायब होना, इसका मतलब यह बड़ा घोटाला हो रहा है। कर्मचारियों को मिलीभगत के बिना रजिस्टर गायब नहीं हो सकता तथा एक धर्मशाला का पट्टा नगर पालिका द्वारा जारी करने मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी एवं घर-घर कचरा संग्रहण मामले में लापरवाही

नहीं बरतने के निर्देश भी ठेकेदार शुभम शर्मा को दिए। गुप्ता ने कहा कि हेरिटेज हवेलियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यह पर्यटक का मुख्य दर्शनीय स्थल है एवं इसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ एवं इन्हें रात के अंधेरे में गिराने की सजिश्न से की जा रही है। उनको बेनकाब किया जाएगा। विदेशी टूरिस्ट के नाम पर मंडावा 30वें स्थान

पर है। जो अपने आप में एक राजस्थान के पर्यटक स्थलों में विशेष महत्व रखता है। आज हमारे राजस्थान के पर्यटक स्थलों की चर्चा विदेश में गूज रही है। उसमें मंडावा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हवेलिया गिरने को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। केके गुप्ता ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नालियों की सफाई, सड़कों के अतिक्रमण हटाने, जानवरों को गौशाला में छुड़वाने, स्ट्रीट लाइट, सड़कों पर पानी भराव, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, हवेलियों का जीर्णोद्धार व तोड़फोड़ ना हो, सर्वजनिक टॉयलेटों की सफाई दिन में, आमजन को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय रहते हो, सड़क किनारे लगने वाले डेलों के लिए स्थान निर्धारित करने आदि के दिशा निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी, इस दौरान सीवरेज कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पुंज वर, विनय रेड्डी, वरिष्ठ प्रारूपकार आनंदबिहारी सोलंकी, सफाई निरीक्षक सत्यनारायण बावलिया, ठेकेदार शुभम शर्मा, पार्षद राजकुमार सैनी, इब्राहिम रंजित, नंदकिशोर यादव, पालिका उपाध्यक्ष नवाब खत्री भी मौजूद थे।

शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा

लुटेरी दुल्हन सहित दलाल व दो अन्य साथी गिरफ्तार, साढ़े चार लाख रुपए बरामद

अजमेर, (कास)। शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा मंगलवार को राजकीय रेलवे पुलिस ने किया। पुलिस ने महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साढ़े चार लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

जोआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उदयपुर निवासी रिटायर्ड गाई 60 वर्षीय शोभालाल माली ने 30 अगस्त को मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसके दोस्त छगनलाल माली ने उसे अनिल जैन से मिलवाया था। अनिल ने झारखंड की गरीब परिवार की लड़की से बेटे की शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए पहले 2 लाख रुपए विवाह स्थल

■ पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया, पूछताछ जारी

और खर्च के नाम पर ले लिए गए। पीड़ित को 30 अगस्त को लड़की से मिलाने के बहाने अजमेर रेलवे स्टेशन बुलाया गया। वहां अनिल ने रिसेप्शन और गहनों के बहाने साढ़े चार लाख रुपए नगद ले लिए। थोड़ी देर बाद उसने फोन कर बताया कि लड़की पैसे लेकर भाग गई। इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य दलाल उदयपुर निवासी अनिल जैन है, जबकि अन्य दो आरोपी धनबाद (झारखंड) की महिला और उसका साथी बताए जा रहे हैं।

मुख्य आरोपी अनिल जैन को

जयपुर से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1.30 लाख रुपए बरामद किए। उसकी सूचना पर धनबाद निवासी प्रियंका मैरी अलायंस और मेघनाथ को अजमेर दरााह से 2.70 लाख रुपए मिले। जांच में सामने आया कि अनिल की शादी भी चार साल पहले धनबाद की एक महिला से हुई थी। वहीं से उसकी मुलाकात प्रियंका और मेघनाथ से हुई और तीनों ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने का सिलसिला शुरू किया। कई मामलों में ये दुल्हन बनकर शादी करवाते और फिर गहनों व पैसे के साथ फरार हो जाते। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरोह के अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है और आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया गया है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय है और कई लोगों को इसी तरह ठग चुका है।

ऑपरेशन थिएटर में बुजुर्ग महिला की कथित मौत का आरोप



हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझावश की।

झुंझुनू, (निर्स)। एक बार फिर शहर के रोड नंबर तीन पर स्थित एक निजी अस्पताल में हंगामा हुआ है। इलाज के दौरान ऑपरेशन थिएटर में हुई बुजुर्ग महिला की कथित मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। समझावश की कोशिश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक झुंझुनू शहर के रोड नंबर एक सैनिक नगर निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पतासी देवी को उनके परिजनों ने अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के लिए 30 अगस्त को भर्ती करवाया था। जिसका ऑपरेशन एक सितंबर, यानि कि सोमवार को होना था। परिजनों का कहना है कि निर्धारित समय पर सोमवार को डॉक्टर पतासी

■ बुजुर्ग महिला की कथित मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, पुलिस पहुंची

देवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, लेकिन करीब एक घंटे बाद पतासी देवी के बेटे सीताराम को डॉक्टरों ने बताया कि पतासी देवी के हार्ट में काम करना बंद कर दिया है। जिस पर सीताराम ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। सीताराम का दावा है कि उसके द्वारा दी गई धमकी से डरकर डॉक्टरों ने उससे झूठ बोला और कहा कि वे सीपीआर के जरिए पतासी देवी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद

उसकी मां को वेंटिलेटर पर ले लिया गया, लेकिन मिलने नहीं दिया। मंगलवार सुबह डॉक्टरों ने उसकी मां की मौत की जानकारी दी। जिसके बाद सीताराम और उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि इलाज में बरती गई लापरवाही से उसकी मां की जान चली गई। हंगामे की सूचना पर शहर कोतवाल हरजिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई ना होने तक परिजन महिला का शव ना लेने पर अड़े रहे। हुए शाम को परिजन समझावश पर शांत हुए और शव को लिया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई।

मंदिर में हुई चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निर्स)। चारभुजानाथ मंदिर से चोरी हुए चांदी के छत्र का खुलासा आसीद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं नगरवासियों के सहयोग से 12 घंटे में करते हुए एक जने को पकड़ लिया है।

आसीद थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बताया कि आसीद में श्री चारभुजानाथ मंदिर से चोरी हुए चांदी के छत्र को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रह्लाद

■ तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से चोरी हुआ चांदी का छत्र बरामद हुआ

नाथ योगी के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल व पुलिस उपा अधीक्षक ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन में आसीद थानाधिकारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम में थानाधिकारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में इस टीम में हेड कांस्टेबल श्रवण



आसीद पुलिस ने चोरी के आरोप में एक जने को पकड़ा।

कुमार और कांस्टेबल कालूराम, महादेव सिंह, मूल सिंह, महेंद्र सिंह और गणपत शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में करीब 25 साल का एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल मिला। पुलिस ने फुटेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद जनता और पुलिस के सहयोग से आरोपी की पहचान हुई। आरोपी प्रह्लाद नाथ को पीडब्ल्यूडी चौराहे के पास एक होटल के सामने से

हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान उसके बैग से चोरी हुआ चांदी का छत्र बरामद हुआ। मंदिर के पुजारी राजाराम वैष्णव ने मौके पर ही छत्र की पहचान की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरालब है कि पुजारी राजाराम वैष्णव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब सवा ग्यारह बजे एक अज्ञात व्यक्ति मंदिर में आया और मूर्ति पर लगा चांदी का करीब एक किलो वजन छत्र चुराकर ले गया है।

अजीतगढ़ तालाब की पाल पर चादर चली

भीम, (निर्स)। उपखंड क्षेत्र के अजीतगढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के अजीतगढ़ तालाब की पाल पर स्थित पुल ओवरफ्लो होने से ग्रामीणों एवं स्कूली विद्यार्थियों के लिए खतरा बन गया है। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अब हालात ऐसे हैं कि विद्यार्थी जान जोखिम डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं।

सरेली घाटी, मियालाखेत के विद्यार्थी इस पुल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं, लेकिन गत दिनों हुई लगातार बारिश के कारण अजीतगढ़ तालाब की पाल पर ओवरफ्लो पानी चल रहा है। विद्यार्थी हर दिन इस मार्ग से गुजर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हेमंटरसिंह ईश्वरसिंह, धारा सिंह, रमेश कुमार भाट, किशन सिंह, धर्मेन्द्र कुमार भाट नारायणसिंह गिरधारीसिंह हेमसिंह आदि ग्रामीण ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने साथ ही सुरक्षित और स्थायी पुल बनाने की मांग की है। वर्तमान में क्षेत्र में अल्पविक बर्षा होने से आस-पास के तालाब नदी नाले एवं अन्य जलाशय अपनी भराव क्षमता पूर्ण कर ओवरफ्लो

■ सरेली घाटी, मियालाखेत के विद्यार्थी इस पुल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं

■ गत दिनों हुई बारिश के कारण अजीतगढ़ तालाब की पाल पर ओवरफ्लो पानी चल रहा है।

चलने पर जल संसाधन विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी कर जागरूक किया है।

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु व्यास ने आमजन को सूचित करने के लिए प्रेस नोट जारी कर बताया कि कुंडेली बांध,कालाभाटा बांध, नीमारबांध, भीम तालाब, भीम रण्ट, भोपालसागर तालाब, तालाब के नीचे डाउनस्ट्रीम में खारी नदी, नेखाड़ी नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करें, ताकि किसी प्रकार की जनहानि एवं असुविधा नहीं हो।

ग्राम भाबरू में भारी बारिश से मकान ढहा, परिवार बेघर हुआ

पावटा, (निर्स)। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में प्रतिदिन हो रही झमाझम बारिश के कारण जर्जर एवं मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं

■ प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की लगाई गुहार

है। क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई क्षेत्रों में मकान ढहने, खेतों को नुकसान की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में विराटनगर उपखंड की ग्राम पंचायत भाबरू, योगी मोहल्ला निवासी गोवर्धन योगी का मकान भारी वर्षा के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण उनका परिवार बेघर हो गया है। गनीमत यह रही कि इसमें किसी तरह की घटनाएं सामने नहीं हुईं। गोवर्धन योगी ने बताया कि उनका मकान बारिश से धराशायी हो गया, जिसमें शेरलू सामान समेत आशियाना बर्बाद हो



ग्राम पंचायत भाबरू में एक मकान भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया।

गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास इस मकान के अलावा और कोई आसरा नहीं है। परिवार बेहद गरीब है और अब उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। घटना की सूचना मिलते ही

ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इस परिवार की मदद के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। बारिश का कहर अभी थमा नहीं है और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।

प्रोसेस हाउस पर काला पानी छोड़ने का आरोप

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले में प्रोसेस हाउस ग्रामीणों को काले पानी की सजा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सोना प्रोसेस हाउस का है, जहां काला पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रोसेस हाउस बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोना प्रोसेस हाउस पर काला पानी छोड़ने का ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सोना सिलेक्शन फैक्ट्री के बाहर हाथों में काला पानी लेकर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री बंद करने की चेतावनी के साथ प्रदर्शन फिलहाल जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रोसेस हाउसों द्वारा छोड़े जा

■ ग्रामीणों ने प्रोसेस हाउस बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया

रहे काला पानी से गांव के आसपास पशुओं की मौत हो रही है, कुओं का पानी तक कला हो गया है। कौरों की झोपड़ियां के ग्रामीण प्रोसेस हाउसों की तानाशाही के चलते काले पानी की सजा पाने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग पुष्पा कार्यवाही नहीं कर रहा है।

दो गाइड सम्मानित

राजसमंद, (निर्स)। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रपति अवाड स्काउट-गाइड रोवर-रंजर रेली में जिले से दो गाइड को राष्ट्रपति अवाड से सम्मानित किया गया। इस वर्ष जिले से लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल की दो गाइड्स मेघना हींगड पुत्री अशोक हींगड और कृत्वी कावडिया पुत्री हेमंत कावडिया को यह सम्मान मिला। 31 अगस्त को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रपति अवाड से अलंकृत किया।

राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता शुरु

राजसमंद, (निर्स)। जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमंद के सभागार में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का पथ्य शुभारंभ हुआ। इस उत्सव में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुल 228 युवा कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने किया। कला उत्सव में छात्र-छात्राएं गायन, वादन, नृत्य, नाटक, कहानी वाचन और दृश्य कला जैसे विविध श्रेणियों में अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं।

बांसड़वाड़ा की पहाड़ियों पर लैपर्ड का मूवमेंट, लोगों में दहशत

स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया, वन विभाग से रेस्क्यू की मांग

डूंगरपुर, (निर्स)। शहर के बांसड़वाड़ा मोहल्ले के पीछे पहाड़ियों पर एक बार फिर से लैपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। लोगों ने लैपर्ड का वीडियो भी बना लिया। लोगों का कहना है पहाड़ियों पर एक नहीं 3 लैपर्ड हैं, जो कई बार नजर आते हैं। इससे हमेशा की कॉलोनी में लोगों में डर बना रहता है। लोगों ने वन विभाग से तीनों लैपर्ड का रेस्क्यू करने

■ लोगों का कहना है पहाड़ियों पर एक नहीं 3 लैपर्ड हैं, जो कई बार नजर आते हैं

की मांग की है। बांसड़वाड़ा डूंगरपुर नगर परिषद के पीछे एक पहाड़ी पर बसा है। इसके पीछे की तरफ उदयविलास की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर आए दिन लैपर्ड और उसका कुनबा दिखाई दिया

है। गत देर शाम के समय पहाड़ी पर एक लैपर्ड पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ दिखा। जिस पर लोग डर गए। लैपर्ड पहाड़ी से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाते दिख रहा है और फिर एक पेड़ की पीछे झाड़ियों में छुप गया। मौजूद

लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। लोगों ने कहा कि पिछले दिन एक साथ 3 लैपर्ड दिखाई दिए थे। आए दिन इस पहाड़ी के ऊपर की तरफ लैपर्ड दिखता है। उनके नीचे कॉलोनी ने आने पर कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए हमेशा डर रहता है। बांसड़वाड़ा के लोगों ने वन विभाग से लैपर्ड का रेस्क्यू करने की मांग की है।

करंट से बालिका की मौत

बॉली-बामनवास, (निर्स)। क्षेत्र की ग्राम पंचायत लाखनपुर के ग्राम गोठड़ा में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एक 12 वर्षीय बालिका चेतन वर्मा की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लाखनपुर ग्राम पंचायत के सरपंच सियाराम मीणा ने बताया कि मंगलवार को करीब तीन बजे श्यामलाल वर्मा निवासी गोठड़ा की 12 वर्षीय बालिका चेतन वर्मा अपने घर के बाहर कुएं पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान बालिका द्वारा मोटर चालू करते समय स्टार्टर में करंट आ गया, इससे बालिका बेहोश हो गई। परिजनों द्वारा बालिका को बॉली चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

■ बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर टोका तो आरोपियों ने भाड़ियों से मारपीट की थी, वारदात को एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है

वीडियो भेजकर छेड़छाड़ करते थे। जब उसकी बहन ने यह बात बताई तो उसने आरोपियों को उलाहना दिया। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन्हें धमकी से बुलाकर मारपीट की। वारदात को एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई सुस्त है इस कारण उनके हौसले बुलंद हो गए हैं।

भीलवाड़ा, (निर्स)। बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर टोका तो आरोपियों ने भाड़ियों की जमकर मारपीट कर दी। मामला बागीर थाना क्षेत्र में दो भाड़ियों के साथ बेरहमी से मारपीट का है।

पीड़ित कैलाश कौर ने बागीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 27 अगस्त रात को उसे और उसके भाई उदयलाल कौर को उनके ही खेत पर बुलाया गया। आरोपियों ने खेत में मवेशी घुसने का बहाना बनाकर दोनों भाड़ियों को मौके पर बुलाया और वहां करीब एक दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में उदयलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया और हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां हादसा इलाज कर रहे हैं। पीड़ित उदयलाल ने बताया कि आरोपी उसकी बहन को सोशल मीडिया पर फोन करके और अभद्र फोटो-

“शहर चलो अभियान” अंत्योदय की संकल्पना को साकार करेगा

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर शहरी क्षेत्रों में अभियान का निर्णय लिया

जयपुर, 2 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। “शहर चलो अभियान” इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान

■ **मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा में 4 से 13 सितम्बर तक प्री कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये, जिनमें अधिकांश वॉर्डों का दौरा कर पार्षदों से चर्चा करेंगे और समस्याओं को चिन्हित करेंगे।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि “शहर चलो अभियान” से पहले प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं।

के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि इस अभियान से शहरी निकायों में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढीकरण होगा और सेवाओं को नई गति मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान से पहले 4 से 13 सितम्बर तक प्री-कैम्प आयोजित किए जाएं, जिसमें अधिकारी वार्डों का दौरा कर पार्षदों से चर्चा करें और समस्याओं का चिन्हीकरण करें। इससे मुख्य शिविरों के दौरान लोगों को तत्काल और सुगम राहत मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत सफाई व्यवस्था में सुधार, नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, आबारा

पशुओं की पकड़, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव व सौन्दर्यीकरण, सड़क मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण, पीएम सूर्यघर योजना के आवेदन प्राप्त करना, सामुदायिक भवनों, आंगनवाड़ी और विद्यालयों की मरम्मत जैसे कार्य भी अभियान के तहत संपादित किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार

शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वच्छता, पेयजल, सड़क और सीवेज जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि प्रदेश का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शिवाजी सिंह खरौं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अफगानिस्तान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सामग्री में कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, पोर्टेबल वाटर प्यूरीफायर, ओआरएस घोल और विक्तिसा उपभोग्य सामग्रियों सहित 21 टन राहत सामग्री आज काबुल पहुंच गयी।

डॉ. दीपक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे। दोनों देशों के बीच पिछले छह-सात वर्षों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के बाद इनमें नयी ऊर्जा आयी है। अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ-साथ वहां के कुछ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भी भारत की यात्रा की है।

आठ साल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
राज्य सरकार मामले में भू-अभिलेख निरीक्षण पत्र पर पदेनवित्त के लिए विभागीय परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद बोर्ड ने परीक्षा नहीं कराई। वहीं बाद में राज्य सरकार ने अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान शपथ पत्र दायर कर कहा कि उन्होंने 7 मार्च 2019 को विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी कर आदेश की पालना कर दी है। इसके बाद भी यह विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। जबकि परीक्षा के लिए स्वीकृत पदों पर डीपीसी के जरिए कनिष्ठ कर्मियों को पदेनवित्त दे दी है। इसलिए अदालती आदेशों की पालना करवाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रैबैन्सु बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

‘अदालत के आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को दी जाने वाले बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय करके हुए किए जाने वाले भुगतान का साक्ष्य देने और राशि अदा नहीं करने की सूची में दोनों अधिकारियों को हाजिर होने को कहा है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को साल 1997 से नियमितकरणा का लाभ देते हुए उसे बकाया भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई।

के. चन्द्रशेखर राव की बेटी कविता भारत राष्ट्र समिति से निष्कासित

कविता पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पर मूल वजह कविता द्वारा अपने पिता केसीआर को लिखे गए पत्र को बताया जा रहा है, जो लोक हो गया।

हैदराबाद, 02 सितंबर। तेलंगाना की पार्टी, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने अपनी एमएलसी और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीआरएस ने कहा कि हाल के दिनों में कविता के व्यवहार और उनकी गतिविधियों पार्टी के हितों के खिलाफ रही हैं। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और संगठन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीआरएस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने एमएलसी कविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है।

कविता को पार्टी से ऐसे समय में बर्खास्त किया गया है, जब बीआरएस पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। बर्खास्तगी से एक दिन पहले कविता ने उस समय पार्टी के भीतर तुलान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने वरिष्ठ नेता टी. हरीश राव और पूर्व सांसद मेधा कृष्णा रेड्डी पर, उनके पिता चंद्रशेखर राव पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने का आरोप लगाया और दावा किया कि हरीश राव और संतोष कुमार ने उन्हें हाशिये पर धकेलने की साजिश

■ **पत्र में कविता ने अपने पिता को लिखा था, पापा आपको भाजपा के खिलाफ तीखा बोलना चाहिए था, क्योंकि भाजपा की वजह से मुझे कष्ट हुआ था।**

रची। 22 अगस्त को कविता जब विदेश में थीं, तब उन्हें अचानक तेलंगाना बोगू घाना की कर्मिका संघम (टीबीजीकेएस) की मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उन्होंने इसे एक साजिश बताया था और कहा था कि यह कदम पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कविता ने आरोप लगाया था कि टीबीजीकेएस के लिए चुनाव उनकी बिना जानकारी के पार्टी दफतर में हुआ और यह श्रम कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता है। उन्होंने कहा, मैंने केवल पार्टी के अंदरूनी कामकाज पर सवाल उठाया, इसी बात की मुझे सजा दी जा रही है। उन्होंने इसके लिए पार्टी के कुछ लोगों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने यह भी बताया कि बीआरएस की बैठक के बाद जो पत्र उन्होंने अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष को लिखा था, उसका लीक होना उनके खिलाफ माहौल बनने की वजह बना। उस पत्र में कविता ने लिखा था, आप (केसीआर) ने केवल दो मिन्ट बोलें और उसी से कुछ लोग यह अटकलबाजी करने लगे कि भविष्य में

भाजपा से गठबंधन होगा। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगा कि आपको भाजपा के खिलाफ और तीखा बोलना चाहिए था। शायद इसलिए क्योंकि मुझे भाजपा की वजह से ही कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन पापा, आपको और सख्त रख अपनाना चाहिए था।

‘अदालत के आदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को दी जाने वाले बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय करके हुए किए जाने वाले भुगतान का साक्ष्य देने और राशि अदा नहीं करने की सूची में दोनों अधिकारियों को हाजिर होने को कहा है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को साल 1997 से नियमितकरणा का लाभ देते हुए उसे बकाया भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की जमानत बरकरार रखी

उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी

उदयपुर, 2 सितम्बर (का.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत को बरकरार रखा है।

मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी की उम्र अपराध के समय मात्र 19 साल थी और मुकदमा अभी शुरूआती चरण में है, ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत मंजूर करने के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पीडित कन्हैयालाल के बेटे यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर

■ **कन्हैया लाल के पुत्र यश तेली और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग की थी।**

जावेद को हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मौजूद अहम सबूतों की नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर हत्या की साजिश रचने में मदद का गंभीर आरोप है।

आपको बता दें कि जून 2022 में उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की दुकान में आरोपियों मो. रियाज और मो. गौस ने दिनदहाड़े गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था।

हत्या का कारण यह बताया गया कि कन्हैयालाल ने भाजपा की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद संबंधी बयान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। जांच में सामने आया कि कई अन्य लोगों ने हमलावरों को सहयोग दिया, जिनमें से जावेद पर अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से निचली अदालत प्रभावित न हो और जावेद को दी गई जमानत का मतलब यह नहीं कि उसे किसी अन्य राहत का हकदार माना जाए। एनआई और पीडित पक्ष की याचिका खारिज कर अदालत ने निचली अदालत को निष्पक्ष सुनवाई का निर्देश दिया।

पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि मुकदमे में कुल 166 गवाह हैं, जिनमें अब तक केवल 8 की गवाही हुई है। सुनवाई लंबी चल सकती है, इसलिए आरोपी को जमानत से वंचित करना उचित नहीं होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से निचली अदालत प्रभावित न हो और जावेद को दी गई जमानत का मतलब यह नहीं कि उसे किसी अन्य राहत का हकदार माना जाए। एनआई और पीडित पक्ष की याचिका खारिज कर अदालत ने निचली अदालत को निष्पक्ष सुनवाई का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग का पवन खेड़ा को नोटिस

नयी दिल्ली, 02 सितम्बर। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने दो जगह वोटर सूची में नाम होने के आरोप में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है और आठ सितम्बर तक जवाब देने को कहा है।

■ **पवन खेड़ा का नाम दिल्ली के दो क्षेत्रों, काका नगर और डी ब्लॉक जंगपुरा में पाया गया है।**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि खेड़ा का नाम दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 40 के काका नगर के पते पर है और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र 41 के डी ब्लॉक जंगपुरा के पते पर पाया गया है। खेड़ा को भेजे नोटिस में चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एक व्यक्ति के दो जगह से वोटर लिस्ट में नाम होना दंडनीय अपराध है। चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि इस नियम के तहत उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और इसका जवाब निर्वाचन अधिकारी को आठ सितम्बर सुबह 11 बजे तक मिलना चाहिए।

तेज बारिश से भिवाड़ी में अधिकांश इलाके पानी में डूबे

घरों, दुकानों, बैंकों व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में पानी घुसा, सड़कें नदी बनीं

अलवर, 2 सितम्बर। भिवाड़ी में सोमवार रात से लगातार हो रही तेज बारिश ने इस औद्योगिक नगरी को जलमग्न कर दिया है। शहर के अधिकांश इलाके पानी में डूब चुके हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। घरों, दुकानों, बैंकों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में पानी घुस गया है, वहीं सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं।

जानकारी के अनुसार, बारिश का सबसे ज्यादा असर यूआईटी गौरव पथ, सेंट्रल मार्केट, भिवाड़ी बायपास और भगत सिंह कॉलोनी में देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड के आसपास भी हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर भरे पानी के कारण गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे, जिससे वाहन चालक अंदाजे से गाड़ियां चला रहे हैं। खिजुरिवास के पास टोल टैक्स पर हाइवे क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां गहरे गड्ढों में वाहन फंस रहे हैं, जिससे कई

■ **भिवाड़ी-धारुहेड़ा सीमा पर बना चार फीट ऊंचा रैंप पानी में पूरा डूबा।**

किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दोपहिया वाहनों का चलना लगभग असंभव हो गया है। यूआईटी थाने के सामने डेढ़ से दो फीट तक पानी बह रहा है, जिससे थाना भवन भी जलमग्न हो गया है। भिवाड़ी-धारुहेड़ा सीमा पर बना चार फीट ऊंचा रैंप भी पूरी तरह डूब चुका है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल और सुखम टॉवर के सामने करीब पांच फीट पानी भर गया है, जो धारुहेड़ा की ओर फैल गया है। इससे धारुहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। प्रशासन की ओर से जल

निकासी के प्रयास नाकाम साबित हुए हैं। न तो सड़कों पर कोई अधिकारी नजर आ रहा है और न ही सरकारी मशीनरी सक्रिय है।

ऐसे में रोटरी क्लब भिवाड़ी ने राहत कार्य की जिम्मेदारी संभाली है। क्लब की ओर से भिवाड़ी बायपास और भगत सिंह कॉलोनी में ट्रेक्टर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से लोगों को पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अलवर शहर में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। रात को भी बारिश हुई। देर शाम की बारिश से अलवर शहर में कई जगहों पर दो-दो फीट पानी भर गया। बहुत से घरों के अंदर पानी चला गया। कोतवाली थाने के अंदर भी पानी भर गया।

मोदी की पुतिन व जिनपिंग के साथ नज़दीकी पर बौखलाया अमेरिका

वाशिंगटन, 02 सितंबर। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एएससीओ समिट में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की है।

नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजदीकी को नवारो ने रणनीतिक भूल बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह जिनपिंग और पुतिन के साथ घुले-

■ **अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार ने तीनों नेताओं के मेलजोल पर बड़ी हल्की टिप्पणी की**

■ **नवारो ने यह भी कहा कि मोदी को पुतिन व जिनपिंग के नजदीक देखना बेहद खराब और शर्मनाक था।**

मिले, वह देखना शर्मनाक था। उनको समझना होगा कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। नवारो ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एएससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग, मोदी और पुतिन की

देखना निश्चित रूप से खराब था। मुझे लगता है कि भारतीय पीएम को इससे बचना चाहिए था।

नवारो ने भारत के रूख की तुलना अमेरिका के दूसरे व्यापारिक सलाहकारों से की। उन्होंने कहा, भारत ने हमारे साथ जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ की तरह बातचीत नहीं की है। उन्हें बस लगता है कि वे हमारे साथ अपनी मनमानी जारी रख सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे।

■ **नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंद्रु अधिकारी एक दिन के लिए विधानसभा से निलंबित।**

कोलकाता, 02 सितंबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंद्रु अधिकारी को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। यह विशेष सत्र बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उपरीडन की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ब्रज्य बसु

‘पश्चिमी देशों की सारी मेहनत ट्रंप ने बर्बाद कर दी’

वाशिंगटन, 02 सितंबर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन

■ **अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा, पश्चिमी देशों ने कई दशकों की मेहनत के बाद भारत को रूस से दूर किया था।**

■ **जॉन बोल्टन ने कहा, अमेरिका की नीति से हटकर ट्रंप पाकिस्तान व उसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुश करने में लगे हैं।**

ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की है। जॉन बोल्टन का कहना है सोवियत संघ से नजदीकी और चीन से बढ़ते खतरे के बावजूद पश्चिमी देशों ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने दशकों पुरानी सारी मेहनत बर्बाद कर दी।

जॉन बोल्टन ने सोशल मीडिया

‘कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कांग्रेस ने तुल्य की आलोचना की। आप ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आप के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जानबूझकर वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा। केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित, सिसोदिया के खिलाफ अरविंद सूरी तथा आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा गया। आप ने इसे कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का प्रमाण बताया। बात यहीं नहीं रुकी, दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की एक विवादास्पद तस्वीर भी वायरल हुई, जिसमें कांग्रेस नेता देवेन्द्र यादव मंच पर आप की बागी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ खड़े दिखाई दिए।

प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप की जमकर आलोचना की। बोल्टन का कहना है कि ट्रंप आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर रणनीतिक फायदों को खतरे में डाल रहे हैं।

जॉन बोल्टन ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप के कारण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पूर्वी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिल गया है। जॉन बोल्टन के अनुसार, “पश्चिमी देशों ने भारत को सोवियत संघ, यानी रूस और चीन से दूर रखने में दशकों लगा दिए थे। डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति के कारण सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया।”

प्रमुख अमेरिकी वकील ने कहा कि ट्रंप के फैसले का नुकसान पूरे देश को भुगताना होगा। ट्रंप ने अपने निजी फायदे के लिए भारत-पाकिस्तान संबंध रूकवाने का दावा किया है। ट्रंप की विदेश नीति का वो पहलू है जिसे अभी तक नहीं उठाना गया।

उन्होंने कहा कि ट्रंप, अमेरिका की विदेश नीति से अलग हटकर पाकिस्तान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। भारत के शंखे रिश्ते बनाने में अमेरिका को फायदा है।

चीन, रूस नॉर्थ कोरिया व ईरान, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अमेरिका के अहंकारी रवैये के कारण भारत को इस नए वैकल्पिक समूह में शामिल होना पड़ा, लेकिन फिर भी वह उसका मुख्य हिस्सा नहीं है।

भारत ने चीन द्वारा खड़े किए जा रहे इस नए वैश्विक ढांचे की बैठक में ज़रूर हिस्सा लिया, लेकिन वह अभी भी इस गठबंधन के बाहर ही खड़ा है और दोनों नए ध्रुवों से कुछ दूरी बनाए हुए है। वहीं अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते ट्रंप की अखड़ों और हुस्म देने वाली शैली के कारण बिगड़ चुके हैं। चीन के नेतृत्व वाली “कोर फॉर्मेशन” से भारत की दूरी उस समय साफ नजर आई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति के साथ खड़े होकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। भारत बीजिंग में बैठकर चीन की ऐसी सैन्य परेड का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत के लिए ज़रूरी है कि वह अपने सैन्य-शक्ति को इतना मजबूत करे कि चीन की ताकत का सामना कर

सके और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके।

भारत और चीन के बीच दोस्ती के दिखाने के बावजूद तनाव के मुद्दे बने हुए हैं, जिन्हें हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे रूस और चीन के बीच अतट दोस्ती के वादे भी असली मतभेदों को छुपा नहीं सकते। इस बैठक ने दिखा दिया है कि दुनिया के रणनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस नए ढांचे में भारत अलग-थलग लेकिन मजबूत शक्ति केंद्र बनकर खड़ा है। जबकि, पश्चिमी देश और चीन को अगुवाई वाला नया गठबंधन और दो ध्रुवों के रूप में उभर रहे हैं। इस नए ढांचे का सबसे अहम पहलू यह है कि रूस अब एक बड़े खिलाड़ी और पश्चिमी गठबंधन को संतुलित करने वाली ताकत की भूमिका से पूरी तरह बाहर हो चुका है। वह अब चीन का अधीनस्थ बन गया है, चाहे बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश क्यों न हो।

पश्चिमी मीडिया पहले ही इस नए

गठबंधन को “अस्थिरता की धुरी” कहने लगा है, जिसमें चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान मुख्य भूमिका में हैं। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि कोई देश कितनी जल्दी और कितनी बुरी तरह गिर सकता है। कभी निकिता ख्रुश्चव से लेकर लियोनिड ब्रेज़नेव के दौर में रूस दुनिया की महाशक्ति था, हथियारों और विज्ञान-तकनीक दोनों में श्रेष्ठ। लेकिन आज वह ताकत खत्म हो चुकी है। शीतयुद्ध का दौर रूस के लिए एक ज़्यादा गरिमा और ताकत वाला था, बनिस्वत आज के, जब अपने एकमात्र सहायक के रूप में वो चीन से दोस्ती दिखाने को मजबूर है। आज का रूस भूल गया है, जॉन मिल्टन की “पैराडाइज़ लॉस्ट” की वह अमर पंक्ति, जिसमें शैतान कहता है, नरक में जा बचना बेहतर है, बजाय इसके कि स्वर्ग में नौकर बना जाए। यूरोपीय संस्कृति और सोच से जुड़े रहने वाला रूस अब एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है और एक नीते हुए साम्राज्य के ग़लत सपनों के पीछे भाग रहा है।